www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 04 || लखनऊ
शनिवार
04 अप्रैल 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदयः 05:54
सूर्यास्तः 06:25
अधिकतमः 33°00
न्यूनतमः 21°00

पेज 03

विशेष समाचार
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक ... >> पेज 02
भाजपा 'सौदागर' की तरह कर ... >> पेज 04
विंदू दारा सिंह ने 'रामायण' के मेकर्स को दी ...

ईरान ने एफ-35 विमान के मलबे की तस्वीर जारी की

ईरान ने एक विमान के कुछ टुकड़ों की तस्वीर जारी की हैं। ईरान का दावा है कि यह मलबा अमेरिकी एफ-35 विमान का है, जिसे उसने आज गिराया है। इटली के अर्थव्यवस्था मंत्री ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन (ईयू) अपने बजट घाटा नियमों में ढील दे सकता है। अभी ईयू देशों को जीडीपी के 3% से ज्यादा घाटा रखने की इजाजत नहीं है। लेकिन ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए अगर हालात ऐसे ही रहे तो नियमों में बदलाव करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की बड़ी शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम का एक कंटेनर जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल गया है।

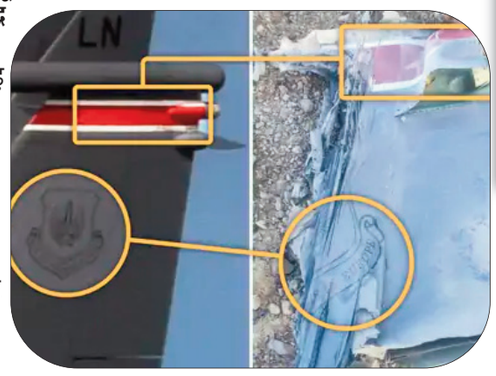

रिपोर्टः अभी भी ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान के अभी भी आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। इसके अलावा ईरान के पास हजारों ड्रोन भी हैं, जिनमें से करीब 50% अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। यह रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे से अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। वहीं रक्षा मंत्री हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% तक कम हो गए हैं।

चीन-पाकिस्तान का 5-पॉइंट प्लान...

- तुरंत युद्धविराम लागू किया जाए
- सभी पक्ष बातचीत शुरू करें
- आम लोगों और सिविलियन ढांचे को निशाना न बनाया जाए
- समुद्री रास्ते (जैसे होर्मुज स्ट्रेट) खुले और सुरक्षित रखे जाएं
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्थायी शांति का समाधान निकाला जाए

ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी

पायलट सुरक्षित, पर अमेरिकी-इजराइली कार्रवाई को लेकर चेतावनी जारी

तमसा संकेत, एजेंसी

ईरान ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार को एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिरा दिया है। हालांकि उसके पायलट को हिरासत में लेने की खबरों से इनकार कर दिया। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान गिरने से पहले पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई और वह ईरान के अंदर ही कहीं उतरा। अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना ने कोहगिलुयेह और बोयेर-अहमद जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर और C-130 हरक्यूलिस विमान लगाए गए। वहीं ईरानी सेना ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए, तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा- अगर हमारे पुल, बिजली घर या ऊर्जा ढांचे को छुआ, तो हम मिडिल ईस्ट में आपके पूरे ठिकाने खत्म कर देंगे ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल हुए।

कुवैत ने कहा है कि हुए ईरानी हमले में एक पावर और डीसैलिनेशन (समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाला) प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है।

एफ-15 की साख पर सवाल

F-15 को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसे अपराजित रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है यानी इसे कभी भी दुश्मन के हवाई जहाज ने नहीं गिराया गया है।

ऐसे में ईरान में इस जहाज का गिरना इसकी साख पर बड़ी चोट है। अमेरिका का F-15 मैक 2.5 (2,800 किमी/घंटा) की अधिकतम गति से उड़ सकता है और 13,000 किलोग्राम से अधिक हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसे अमेरिका की मेकडोनल डगलस कंपनी ने बनाया है। अमेरीकी एयरफोर्स काफी समय से इस विमान का इस्तेमाल करती रही है।

जंग के बीच ट्रम्प सरकार में उथल-पुथल, आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को हटाया

अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रम्प सरकार में कुछ और बड़े अफसरों को निकाले जाने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगला नंबर FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का हो सकता है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के प्लान से जुड़े कई लोगों ने बताया कि और भी अधिकारियों को हटाने पर चर्चा चल रही है इसमें आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज-डीरेमर का नाम भी शामिल है। ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े अधिकारियों को हटाने से बचते रहे थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करना डेमोक्रेट्स और मीडिया के सामने झुकना होगा। कि मिडटर्म चुनाव से पहले किसी कैबिनेट अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा।

ईरान के सबसे ऊंचे पुल पर अमेरिका का हमला

गुरुवार को अमेरिकी-इजरायली हमलों ने मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले से पहले ईरान को ₹पाषाण युग में वापस ले जाने₹ वाली बमबारी करने की चेतावनी दी थी. 136 मीटर ऊंचा B1 पुल अभी भी निर्माणाधीन था और इसे तेहरान को पश्चिमी शहर कारज से जोड़ना था. ईरान के सरकारी मीडिया कारज के अनुसार, हमले में आठ लोग मारे गए और 95 घायल हो गए. पुल के बीच में दो बार हमला किया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हमले के बाद पुल का बड़ा हिस्सा ढहते हुए देखा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फुटेज पोस्ट किया जिसमें B1 पुल से धुआं उठता दिख रहा है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पांच सप्ताह के युद्ध को समाप्त करने के लिए मेज पर नहीं आया तो और विनाश होगा.

ईरान में मेडिकल फैसिलिटी पर हमले बढ़े

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ईरान में हेल्थ फैसिलिटी पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। WHO के मुताबिक, 1 मार्च के बाद से ईरान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 20 से ज्यादा हमलों की पुष्टि हुई है, जिनमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है।

"कंपनी ने बताया कि ये सभी जहाज लारक द्वीप के रास्ते से गुजरे। इसका मतलब है कि कई देश ईरान से बातचीत कर रहे हैं, ताकि उनके जहाज सुरक्षित तरीके से गुजर सकें। इससे आने वाले दिनों में जहाजों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह बढ़ोतरी अभी भी सामान्य स्तर से काफी कम है। युद्ध शुरू होने से पहले, 28 फरवरी तक रोजाना करीब 130 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे।

ईरान की चेतावनी- पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकाने तबाह करेंगे

ईरान की सेना ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए, तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा- अगर हमारे पुल, बिजली घर या ऊर्जा ढांचे को छुआ, तो हम आपके पूरे क्षेत्र के ठिकाने खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

फ्रांस और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने हॉर्मुज रूट को लेकर बात की

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग को फिर नॉर्मल करने पर बात की। इससे पहले कल ब्रिटेन की अध्यक्षता में 60 देशों ने होर्मुज रूट खोलने को लेकर ऑनलाइम मीटिंग की।

फास्ट न्यूज

महिला आरक्षण पर संसद में 16 अप्रैल से चर्चा

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा। ताकि लोकसभा सीटों की संख्या 816 करने से संबंधित विधेयकों को पारित किया जा सके और महिलाओं के आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। सरकार ने यह फैसला गुरुवार को लिया। 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े अहम बिल पर चर्चा की जाएगी।

आईएनएस तारागिरी नेवी में शामिल हुआ

नई दिल्ली। INS तारागिरी शुक्रवार को विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी में शामिल हुआ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस सेरेमनी में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह रेस्क्यू ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो। हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। INS तारागिरी की कमीशनिंग से हमारी नेवी की ताकत और बढ़ेगी। तारागिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17-ए के तहत तैयार किया है। वॉरशिप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एमएफस्टार(रडार), मीडियम रेंज सर्फेस टु एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है।

पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी अरेस्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। वह बेंगलुरु भागने की फिराक में था। इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। वह 2011 में AIMIM का उम्मीदवार रह चुका है। मोफक्करुल पर आरोप है।

'खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं'

डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का मैसेज

प्रतिक्रिया

तमसा संकेत, एजेंसी

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा- मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी को ये मेरा संदेश है। राघव ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे AAP को क्या नुकसान हुआ? उन्होंने AAP को चेतावनी दी कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा।

उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सांसद राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर रिएक्शन दिया।

हालांकि, राघव ने न तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और न ही पार्टी छोड़ने या आगे की रणनीति को लेकर कुछ कहा।

>> (शेष पेज 04 पर)

हमारे यहां सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता : योगी

दंगाइयों की संपत्ति गरीबों में बांट देते हैं, असम में दो रैलियां कीं

योगी ने असम की बरपेटा विधानसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास के लिए चुनावी रैली की।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। 'हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगियों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। लेकिन, भाजपा की डबल इंजन की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। किसी धर्म से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों और दलितों में बांट दी जाती है।' ये बातें सीएम योगी ने असम में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को कहीं। उन्होंने यहां दो रैलियां कीं। इनमें बरपेटा से एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास और बरछला सीट पर विटुबरन शर्मा के लिए वोट देने की अपील की। कांग्रेस और यूडीएफ ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों की एंट्री करवाकर यहां की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम किया। असम के लोगों के मकान, जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया। विकास और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। असम में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर कराने की व्यवस्था की जा रही है। यहां विकास के बड़े-बड़े काम देखने को मिल रहे हैं। एनडीए का संकल्प है कि असम को लैंड जिहाद और लव जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे, यहां घुसपैठ नहीं होने देंगे। कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे।

>> (शेष पेज 04 पर)

"योगी ने कहा- डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान करती है। यह केवल डबल इंजन सरकार ही कर सकती है।

यूपी दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त और माफिया मुक्त है

यूपी में बीते 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यूपी दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त और माफिया मुक्त है। वहां विकास कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। असम में पहले गरीब का राशन विदेशी घुसपैठिया खा जाते थे। ये घुसपैठ कांग्रेस कराती थी। कांग्रेस दंगा कराती थी, लेकिन भाजपा दंगाइयों को सबक सिखा रही। भाजपा की सरकार जहां भी आई है, ऐसी ही शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई है। पहले यूपी में महीनों तक कर्फ्यू लगता था। जो काम 500 साल में नहीं हो पाया। आज देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है।

जीत : ममता ने कहा- वोटर लिस्ट में घुसपैठिए तो मोदी कैसे जीते, पहले वे इस्तीफा दें

असम में यूसीसी लाएंगे, इससे आदिवासी बाहर रहेंगे : शाह

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम/गुवाहाटी/चेन्नई। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलपाड़ा में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में UCC लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई चार शादी नहीं कर सकेगा। UCC में कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी UCC लगेगी लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनके वोट से जीत चुके हैं। ऐसे में पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ममता ने दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले इस तरह किए गए।

>> (शेष पेज 04 पर)

शाह बोले- असम में यूसीसी लाएंगे

गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलपाड़ा में कहा कि असम के युवा कहते हैं कि घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इतनी सारी आबादी बढ़ती है रोके कैसे। उनसे कहना चाहता हूं हम असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाएंगे। अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा। UCC में कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी UCC लगेगी लेकिन आदिवासियों को UCC से बाहर रखा जाएगा। UCC किसके लिए लगाना है हमें मालूम है। गृह मंत्री ने कहा कि BJP ने असम में शांति बहाल की, लेकिन अगर 9 अप्रैल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी सीट जीतती है।

"शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने इसे बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक बन गईं। उन्होंने कहा- आदिवासियों के विकास के लिए पीएम और असम सीएम ने एक रोडमैप तैयार किया है। इसे आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए बीजेपी को वोट दें।"

अन्नामलाई बोले- पार्टी ने प्रचार का काम दिया है, पूरा करूंगा

BJP नेता के अन्नामलाई ने केरल के कन्नूर में कहा- इस चुनाव में, मेरा रोल पूरे तमिलनाडु में कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करना है। पार्टी ने मुझे पुडुचेरी और केरल में प्रचार की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद मुझे पूरे तमिलनाडु में सभी BJP और NDA कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करना है। पार्टी ने मुझे यही ज़िम्मेदारी दी है। मैं वह जिम्मेदारी पूरी करूंगा।

कांग्रेस ने तमिलनाडु में 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

कांग्रेस ने तमिलनाडु में 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। श्रीपेरंबदूर विधानसभा सीट से कांग्रेस PCC चीफ के.सेल्वापे-रुंथगई और कृष्णगिरी से पूर्व MP डॉ. ए चेल्ला कुमार चुनाव लड़ेंगे। मेघालय के पास गारो हिल्स में हाल ही में हुई हिंसा पर शाह ने कहा कि घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं से शादी करके गारो काउंसिल में सत्ता हथियाने की कोशिश की।

भारत को मिली तीसरी परमाणु सबमरीन

अरिहंत और अरिघात के बाद आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल

तैयारी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना में शुक्रवार को तीसरी परमाणु सबमरीन INS अरिदमन कमीशन की गई। इससे पहले INS अरिहंत (2016) और INS अरिघात (अगस्त 2024) को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अरिदमन को कई महीनों के ट्रायल के बाद केरल स्थित नौसैनिक अड्डे पर नौसेना को सौंपा गया। INS अरिदमन को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर (SBC) में तैयार किया गया है। इससे न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता और मजबूत हुई है। यह देश के गोपनीय न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कार्यक्रम SSBN का हिस्सा है। इस कैटेगरी की

सबमरीन परमाणु हथियार ले जाने और लंबे समय तक समुद्र में तैनात रहने में सक्षम होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के नौसैनिक अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि इस संबंध में नौसेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से फिलहाल आधिकारिक बयान नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है-अरिदमन।

सम्पादकीय

पाषाण युग का सच !

क्या पाषाण युग में रहने वाले लोग दूरी तक मार करने वाली मिसाइल, अत्याधुनिक संचार प्रणाली, चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक आविष्कार कर सकते हैं या इन सबसे बढ़कर परमाणु हथियार बना सकते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नयी धमकी देते हुए कहा है कि 'अगले दो से तीन हफ्तों में, हम उन्हें पाषाण युग में वापस भेज देंगे, जहां वे वास्तव में हैं।' पाठक जानते हैं कि ट्रंप इससे पहले ईरान के लोगों को बेहद खतरनाक बताते हुए ईरान जैसे देश को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की बात भी कह चुके हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार है और इसकी वजह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर बड़ा खतरा है, इसी बहाने के साथ इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला बोला था और उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी थी। जब इंसान सभ्यता की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस समय के कबीलाई जीवन में इसी तरह का व्यवहार दो कबीलों में किया जाता था। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दूसरे कबीले के नेता को मार दो और फिर उसके लोगों से कहो कि हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। उससे भी पहले जो पाषाण युग हुआ था, जिसका जिक्र ट्रंप इस सदी में कर रहे हैं, उस युग में पत्थर से हथियार बनाने का हुनर इंसान ने सीख लिया था, जिसके बूते अब वो जंगली जानवरों से खुद को बेहतर बताने लगा था। जानवरों के पास उनके पंजे और नाखून ही हुआ करते थे, इंसान के पास पंजे, नाखून के साथ अब औजार भी थे। उनके बीच फर्क केवल इन्हीं औजारों का ही था। बाकी प्रवृत्ति दोनों की एक जैसी ही थी कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए दूसरे को मार डालो। लड़ाई के नियम-कायदे नहीं होते थे, ताकत और ही मायने रखती थी। कोई कमजोर है, निहत्था है, लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं, लड़ाई की जरूरत है या नहीं, ऐसे सवालों में उलझे बिना केवल अपने फायदे के लिए हमले होते थे। इस लिहाज से देखें तो आज ईरान नहीं अमेरिका पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस कबीले के मुखिया के तौर पर जहां मर्जी वहां हमला कर रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध पांचवे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, और अब तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में ट्रंप ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन का ऐलान किया तो सभी को लगा कि शायद युद्ध खत्म करने की बात कही जाएगी, इस वजह से शेयर बाजार भी चढ़ गया। लेकिन ट्रंप के भाषण में अब तक सोशल मीडिया और मीडिया में कही गई बातों का दोहराव ही था। यह बिल्कुल साफ़ हो गया कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के पास कोई रणनीति नहीं है और वह पूरी तरह से इज़रायल लॉबी की गिरफ़्त में है। इस युद्ध के कारण दुनिया में पहले ही काफी तबाही हो चुकी है और अब नजर आ रहा है कि युद्ध लंबा खिंचेगा और भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों के लिए आर्थिक चुनौतियां गंभीर होती जायेंगी। ऐसे में मोदी सरकार को अब वाकई संकट से निपटने के लिए कमर कस लेना चाहिए। अपने भाषण में ईरान को बर्बाद करने का दावा करते हुए ट्रंप ने कहा कि उसकी नौसेना 'नष्ट' हो गई है और उसकी वायुसेना 'खंडहर' हो गई है। उनके अधिकांश नेता अब मर चुके हैं। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है, और उनके हथियार, कारखाने और रॉकेट लॉन्चर टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। जब यह सब कहा जा रहा था, उस समय ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागीं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी अमेरिका हमारे बारे में पूरी तरह जानता नहीं है। वैसे ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में पूर्व राष्ट्रपतियों का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी भागीदारी एक वर्ष, सात महीने और पांच दिन तक चली। द्वितीय विश्व युद्ध तीन वर्ष, आठ महीने और 25 दिन तक चला। कोरियाई युद्ध तीन वर्ष, एक महीने और दो दिन तक चला। वियतनाम युद्ध 19 वर्ष, पांच महीने और 29 दिन तक चला। इराक युद्ध आठ वर्ष, आठ महीने और 28 दिन तक चला। हम इस सैन्य अभियान में 32 दिनों से हैं। और ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वास्तव में अब कोई खतरा नहीं है। यानी पहले के अमेरिकी नेतृत्व ने लंबे युद्धों में हिस्सा लिया, जबकि ट्रंप केवल 32 दिनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध अगले 'दो से तीन सप्ताह' तक चलेगा। यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी बिजली प्लांट पर हमला करेगा। शायद ट्रंप अब तक समझे नहीं कि ईरान ऐसी धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप के संबोधन से पहले ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को संबोधित एक खुला पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वे 'गढ़ी हुई कहानियों' से परे देखें और यह सवाल करें कि मौजूदा युद्ध वास्तव में किसके हितों की सेवा कर रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लिखा, 'अमेरिकी लोगों के हितों में से कौन से हित वास्तव में इस युद्ध द्वारा पूरे हो रहे हैं? क्या निर्दोष बच्चों का नरसंहार, कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनियों का विनाश, या किसी देश को 'पत्थर के युग' में वापस भेजने की डींग हांकना, अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा कर रहा है?' उन्होंने कहा, 'ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे- जिसमें ऊर्जा और औद्योगिक सुविधाएं शामिल हैं, पर हमला सीधे ईरानी लोगों को निशाना बनाता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पर विपक्ष का विरोध - आशंकाएं और वास्तविकता

संसद में सरकार को घेरने और जनमत को प्रभावित करने के लिए विपक्ष अक्सर ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। इससे बहस तो होती है लेकिन कई बार सार्थक समाधान पीछे छूट जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएपीएफ जैसे संवेदनशील विषय पर निर्णय लेते समय संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

भारत में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली और आपदा प्रबंधन तक, इन बलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब भी इनके ढांचे, सेवा शर्तों या अधिकारों से जुड़ा कोई नया विधेयक या सुधार प्रस्ताव सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा होती है लेकिन हाल के समय में देखा गया है कि विपक्ष इन प्रस्तावों का मुखर विरोध कर रहा है। यह विरोध किन कारणों से प्रेरित है, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहली चिंता संघीय ढांचे (फेडरल स्ट्रक्चर) को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के माध्यम से राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप बढ़ा सकती है। यदि किसी विधेयक में बलों को अधिक स्वायत्तता या सीधे हस्तक्षेप के अधिकार दिए जाते हैं, तो यह राज्यों की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी को कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि कई विपक्षी दल इसे राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बलों के कर्मियों के अधिकारों और कल्याण से जुड़ा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सुधार के नाम पर अनुशासन और नियंत्रण को तो मजबूत कर रही है, लेकिन जवानों की समस्याओं—जैसे लंबी ड्यूटी, मानसिक तनाव, वेतन विसंगतियां और पेंशन—पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि किसी विधेयक में इन मुद्दों का संतुलित समाधान नहीं होता तो उसका विरोध स्वाभाविक है। तीसरा पहलू राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका है। विपक्ष को डर है कि सीएपीएफ का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को दबाने या चुनावी लाभ के लिए किया जा सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में सुरक्षा बलों की निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी ऐसे प्रावधान पर सवाल उठना लाजिमी है जो इस निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। यह भी सच है कि कई बार विरोध का कारण केवल नीतिगत असहमति नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति भी होती है। संसद में सरकार को घेरने और जनमत को प्रभावित करने के लिए विपक्ष अक्सर ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। इससे बहस तो होती है लेकिन कई बार सार्थक समाधान पीछे छूट जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएपीएफ जैसे संवेदनशील विषय पर निर्णय लेते समय संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। सरकार को चाहिए कि वह सभी हितधारकों—राज्यों, सुरक्षा विशेषज्ञों और स्वयं बलों के कर्मियों—से व्यापक संवाद करे। वहीं विपक्ष को भी केवल विरोध तक सीमित न रहकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सुधारों पर सहमति और संवाद का रास्ता ही देशहित में सबसे उपयुक्त साबित होगा। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) — जैसे (सीआरपीएफ), (बीएफएफ), (आईटीबीपी), (सीआईएसएफ) और (एसएसबी) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सीमाओं की रक्षा से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने तक, इन बलों ने लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सेवा की है। ऐसे में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक का प्रस्ताव न केवल प्रशासनिक सुधार का विषय है बल्कि यह देश की सुरक्षा संरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य (सीएपीएफ) के कार्य, अधिकार और जवाबदेही को एक समान कानूनी ढांचे में लाना है। वर्तमान में अलग-अलग बलों के लिए अलग-अलग कानून और नियम हैं जिससे समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में जटिलताएं पैदा होती हैं। एक समेकित विधेयक इन समस्याओं को दूर कर सकता है, जिससे संचालन में स्पष्टता और दक्षता आएगी हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चिंता बलों के अधिकारों और कर्मियों के कल्याण को लेकर है। (सीएपीएफ)के जवान लंबे समय से बेहतर कार्य-परिस्थितियों, निश्चित कार्य-घंटों, और पेंशन संबंधी मुद्दों को उठाते रहे हैं। यदि यह विधेयक केवल प्रशासनिक केंद्रीकरण तक सीमित रह जाता है और जवानों की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करता है, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा, संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव को भी समझना जरूरी है। राज्यों की पुलिस व्यवस्था और ष्ट्रक्कस्न के बीच संतुलन बनाए रखना एक संवेदनशील विषय है। यदि केंद्र के अधिकार अत्यधिक बढ़ते हैं तो यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है जिससे संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। इस विधेयक के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, जवानों के मानसिक स्वास्थ्य, परिवार से दूरी, और कठिन परिस्थितियों में काम करने जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ठोस प्रावधान किए जाएं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक एक अवसर है—सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ उन जवानों के जीवन को बेहतर बनाने का, जो दिन-रात देश की रक्षा में लगे हैं। यह तभी सार्थक होगा, जब सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता और शक्ति के साथ संतुलन भी सुनिश्चित किया जाए।

सौरभ वार्ष्णेय

हार्मूज स्ट्रेट को ...

डॉ घनश्याम बादल

रणनीति,औचित्य,वैश्विक निहितार्थ और ट्रंप

इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान के विरुद्ध संभावित या चल रहे सैन्य कदमों को जिस प्रकार से न्यायोचित ठहराया गया, उसने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। अपनी प्रकृति के मुताबिक ही इस संबोधन में ट्रंप ने सुरक्षा, आतंकवाद, सामरिक संतुलन, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा तथा सहयोगी देशों के हितों जैसे अनेक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विशेष रूप से इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने "आवश्यक" और "रक्षात्मक" कदम बताया हालांकि, इस पूरे विमर्श के भीतर कई ऐसे अंतर्विरोध भी मौजूद हैं जो अमेरिकी विदेश नीति की दीर्घकालिक दिशा और उसके प्रभावों पर प्रश्नचिह्न खड़े करते हैं। कभी भीषणतम हमले करने तो कभी युद्ध विराम की बात करने वाले ट्रंप के भाषण का सबसे बड़ा केंद्रीय तत्व राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा। उन्होंने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख कारण बताते हुए आरोप लगाया कि वह आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है और मध्य-पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। इस संदर्भ में उन्होंने यह तर्क दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों, विशेषकर इजराइल, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। यहां ट्रंप की भाषा स्पष्ट रूप से "पूर्व-निरोधात्मक युद्ध" की अवधारणा को समर्थन देती दिखाई देती है जिसमें ख़तरे के पूरी तरह मूर्त रूप लेने से पहले ही सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया जाता है। अपने अजीबो गरीब व्यवहार एवं तर्कों के साथ इजराइल के साथ अमेरिकी गठबंधन को ट्रंप ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य में नैतिक और रणनीतिक दोनों रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इजराइल पर किसी भी प्रकार का खतरा अमेरिका के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को एक साझा सुरक्षा ढांचे के रूप में चित्रित किया लेकिन आलोचकों का मानना है कि इस दृष्टिकोण में क्षेत्रीय जटिलताओं की अनदेखी की गई है और इससे संघर्ष और अधिक गहरा सकता है। हार्मूज स्ट्रेट को 'ट्रंप स्ट्रेट' के नाम से संबोधित करने की चतुराई भरी गलती करने वाले ट्रंप के संबोधन में ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। यहां उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को और मजबूत कर सकता है। यह रणनीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे आर्थिक हित भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि, होर्मुज क्षेत्र को लेकर ट्रंप की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी देखा गया है। पहले जहां अमेरिका अपेक्षाकृत संयमित रुख अपनाता रहा था, वहीं अब वह अधिक आक्रामक और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति की ओर बढ़ता दिखाई देता है। इस बदलाव का एक कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और किसी भी प्रकार की अस्थिरता को अपने हितों के लिए खतरा मानता है। लेकिन यह रणनीति जोखिमों से भी भरी हुई है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय शक्तियों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है लेकिन "हमें हार्मूज की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें इसकी ज़रूरत है, वें उसकी सुरक्षा की चिंता करें" के कथन के बाद ट्रंप का यह भाषण एक बार फिर दुनिया को चकराने वाला है। भविष्य को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण भी उनके भाषण में स्पष्ट रूप से सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता लेकिन यदि उसे अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेगा। यह एक प्रकार की "शर्तीय शांति" की अवधारणा है, जिसमें शांति की इच्छा तो जताई जाती है, लेकिन साथ ही सैन्य कार्रवाई की संभावना को भी खुला रखा जाता है। इस तरह का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अनिश्चितता को बढ़ाता है और संवाद की संभावनाओं को सीमित करता है। अमेरिका में अपने खिलाफ बढ़ते जा रहे विरोध के बीच लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुके ट्रंप ने अपने संबोधन में घरेलू राजनीति को भी अप्रत्यक्ष रूप से साधने का प्रयास किया। उन्होंने अमेरिकी जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनकी सरकार देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए घरेलू समर्थन आवश्यक होता है लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम अक्सर अप्रत्याशित होते हैं और उनका प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। निष्पक्ष व आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप का यह पूरा विमर्श कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ईरान से उत्पन्न खतरा इतना तात्कालिक और गंभीर है कि सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया जा सके? दूसरा, क्या इस प्रकार की आक्रामक नीति से क्षेत्र में स्थिरता आएगी या फिर यह और अधिक अस्थिरता को जन्म देगी? तीसरा, क्या अमेरिका अपने आर्थिक और सामरिक हितों को "वैश्विक सुरक्षा" के नाम पर प्रस्तुत कर रहा है? इससे इतर भी इस पूरे परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

देशभक्ति के चित्रण...

डॉ. शैलेश शुक्ला

बॉलीवुड द्वारा गढ़े गए मिथकों को तोड़कर देशभक्ति की भावना को मजबूत करती हैं "धुरंधर 2"

समकालीन हिंदी सिनेमा में देशभक्ति का विषय हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है लेकिन इसके चित्रण का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। लंबे समय तक मुख्यधारा के सिनेमा में देशभक्ति को एक सीमित, भावनात्मक और कई बार रूढ़ छवि के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहाँ नायक अकेले ही सब कुछ बदल देता है, दुश्मन को एक ही रंग में दिखाया जाता है और राष्ट्रप्रेम केवल ऊँचे स्वर में बोले गए संवादों और नाटकीय दृश्यों तक सीमित रह जाता है। इस तरह की प्रस्तुति दर्शकों को तत्काल रोमांच तो देती है, लेकिन वह देशभक्ति की गहराई और उसके वास्तविक अर्थ को पूरी तरह नहीं समझा पाती। ऐसे माहौल में "धुरंधर 2" जैसी प्रवृत्तियाँ एक नई दिशा की ओर संकेत करती हैं, जहाँ सिनेमा स्थापित मिथकों को चुनौती देकर देशभक्ति को अधिक यथार्थवादी, संतुलित और विचारशील रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भारतीय फिल्मों में लंबे समय तक देशभक्ति को एक भावनात्मक नारे की तरह प्रस्तुत किया गया, जिसमें जटिल सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को सरल बना दिया जाता था। इसके कारण दर्शकों के मन में देशभक्ति की एक सतही छवि बनती चली गई, जिसमें त्याग, जिम्मेदारी और नैतिकता की गहराई की बजाय तात्कालिक उत्साह को अधिक महत्व मिला। "धुरंधर 2" इस प्रवृत्ति से हटकर देशभक्ति को केवल युद्ध या सीमा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे नागरिक जीवन, जिम्मेदार आचरण और संस्थागत मजबूती से जोड़ती है। यह दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की मजबूती केवल सैनिकों के साहस पर नहीं, बल्कि नागरिकों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक चेतना पर भी निर्भर करती है। बॉलीवुड के बारे में एक महत्वपूर्ण आलोचना यह भी रही है कि कई फिल्मों में समाज के कुछ वर्गों

और समुदायों का चित्रण एकतरफा या रूढ़ तरीके से किया गया। कभी-कभी यह आरोप लगाया गया कि जानबूझकर कुछ पात्रों को नकारात्मक और कुछ को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज के बारे में एक विशेष धारणा बनती है। यह समझना आवश्यक है कि सिनेमा एक रचनात्मक माध्यम है और इसमें पात्रों का निर्माण कहानी, समय और दृष्टिकोण के आधार पर होता है, लेकिन इसके साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है कि किसी भी समुदाय या वर्ग के बारे में स्थायी पूर्वाग्रह न बनाए जाएँ। "धुरंधर 2" जैसी प्रवृत्तियाँ इस संदर्भ में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती दिखाई देती हैं, जहाँ पात्रों को उनकी परिस्थितियों, व्यक्तित्व और कर्मों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, न कि केवल उनकी पहचान के आधार पर। देशभक्ति के चित्रण में एक और बड़ा मिथक यह रहा है कि यह केवल बाहरी दुश्मन के खिलाफ आक्रामकता से जुड़ी होती है। इस सोच में "हम बनाम वे" की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, जो समाज में विभाजन पैदा कर सकती है। "धुरंधर 2" इस धारणा को तोड़ते हुए यह दिखाने की कोशिश करती है कि सच्ची देशभक्ति केवल विरोध में नहीं, बल्कि निर्माण में निहित होती है।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल बढ़ती अराजकता: लोकतंत्र के लिए चुनौती

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं।

अभिषेक शर्मा पर मैच फीस का 25% जुर्माना

केकेआर के खिलाफ मैच में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला

नई दिल्ली, एजेंसी

सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा पर IPL मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ गुरुवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में उन्होंने IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, जिसके चलते उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है। अभिषेक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। IPL द्वारा जारी बयान के अनुसार, उन्होंने लेवल-1 के अपराध के तहत मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को मंजूर कर लिया है। हालांकि, रिप्ले से कैच पूरी तरह स्पष्ट नहीं लग रहा था, लेकिन तीसरे अंपायर ने अलग-अलग एंगल से जांच करने के बाद अभिषेक को आउट करार दिया। फैसले से असंतुष्ट अभिषेक नाराज होकर मैदान से बाहर जाते नजर आए। अभिषेक अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके और 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए अब इस मामले में आगे कोई औपचारिक सुनवाई नहीं होगी।

अभिषेक का विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करते ब्लेसिंग मुजरबानी।

दरअसल, 8.4 ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो गए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 112 किमी/घंटा की धीमी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर अभिषेक ने पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वेयर लेग की ओर गई, जहां बाउंड्री पर मौजूद वरुण चक्रवर्ती तेजी से अपने दाईं ओर भागे, नीचे झुककर शानदार डाइव लगाई और कैच पकड़ लिया।

आर्टिकल 2.3 के उल्लंघन के दोषी पाए गए अभिषेक

अभिषेक शर्मा को IPL की आचार संहिता के आर्टिकल 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह आर्टिकल आमतौर पर मैच के दौरान 'अनुचित व्यवहार' या खेल भावना के विपरीत कमेंट्स या इशारों से संबंधित होता है। मैच रेफरी ने अभी तक उस घटना का खुलासा नहीं किया है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। हालांकि, माना जा रहा है कि अभिषेक शर्मा ने कैच आउट होने पर थर्ड अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई थी।

सस्पेंशन का भी खतरा

अभिषेक शर्मा के खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जुड़ने का मतलब है कि उन्हें अब अगले मैचों में सावधान रहना होगा। IPL के नियमों के मुताबिक, यदि कोई खिलाड़ी एक निश्चित समय सीमा के भीतर 4 या उससे अधिक डिमेरिट पॉइंट जमा कर लेता है, तो उस पर एक या अधिक मैचों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गुरुवार को हुए इस मुकाबले में अभिषेक की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हराया। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में KKR ने बॉलिंग चुनी। कोलकाता 16 ओवर में 161 रन बनाकर सिमट गई।

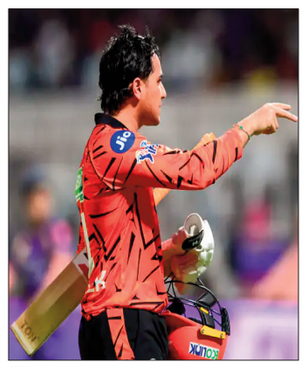
अभिषेक शर्मा आउट होकर पवेलियन लौटते समय गुस्से में दिखे।

मैच रेफरी का फैसला ही अंतिम

IPL के नियमों के अनुसार, लेवल-1 के उल्लंघन के मामलों में मैच रेफरी का फैसला ही अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसमें खिलाड़ी के पास अपील करने का विकल्प नहीं होता।

आरसीबी पेसर नुवान तुषारा कोर्ट पहुंचे

आईपीएल खेलने पर श्रीलंका बोर्ड ने मना किया था, बोले- कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका

- नुवान ने अपना पहला आईपीएल सीजन 2024 में खेल था। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 4.80 करोड़ में खरीद था।
- नुवान ने टी-20 में श्रीलंका के लिए 30 मैचों में 36 विकेट ले चुके हैं।

कोलंबो, एजेंसी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं देने का आरोप लगाते हुए खेलने की अनुमति मांगी है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने कोलंबो जिला अदालत में याचिका दाखिल की है। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट से IPL 2026 में खेलने के लिए NOC जारी करने की मांग की है।इस मामले की शुरुआती सुनवाई हो चुकी है और अगली तारीख 9 अप्रैल तय की गई है। बोर्ड ने तुषारा को NOC देने से इनकार करते हुए कहा कि वह तय फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि तुषारा का कहना है कि वे पहले 2024 और 2025 सीजन में इसी फिटनेस के साथ खेल चुके हैं और तब उन्हें NOC मिल चुका था। ताकि उन्हें IPL समेत विदेशी लीग में खेलने की अनुमति मिल सके। उनका कहना है कि जब उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना जाना था, तब फिटनेस के आधार पर NOC रोकना गलत है। तुषारा ने कहा कि अगर उन्हें NOC नहीं मिली तो IPL टीम उन्हें बदल सकती है। इससे उनके करियर और कमाई दोनों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कोर्ट से अंतरिम और स्थायी आदेश की मांग की है।

कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी

तुषारा ने कोर्ट में बताया कि उनका बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया है। उन्होंने पहले ही इसे आगे नहीं बढ़ाने और इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने की जानकारी दे दी थी। उनका कहना है कि जब उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना जाना था, तब फिटनेस के आधार पर NOC रोकना गलत है। तुषारा ने कहा कि अगर उन्हें NOC नहीं मिली तो IPL टीम उन्हें बदल सकती है। इससे उनके करियर और कमाई दोनों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कोर्ट से अंतरिम और स्थायी आदेश की मांग की है।

फास्ट न्यूज

फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने देने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं।

1500 करोड़ कमाने वाली चौथी फिल्म बनी धुरंधर 2

मुबंई। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने भारत में 961 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म अब 1000 करोड़ रुपए नेट क्लब के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को फिल्म का 19 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन हुआ। जियो स्टूडियोज के मुताबिक, भारत में फिल्म का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1134 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जबकि ओवरसीज में फिल्म का 367 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1501 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बता दें कि ग्रॉस कलेक्शन टिकट से कुल कमाई और नेट कलेक्शन टैक्स के बाद की कमाई होती है। दंगल (2070 करोड़ रुपए), बाहुबली 2 (1788 करोड़ रुपए) और पुष्पा 2 (1742 करोड़ रुपए) के बाद धुरंधर 2 दुनिया भर में 1500 करोड़ रुपए कमाने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति पत्नी के थप्पड़ से उबर रहे : ट्रम्प

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर उनकी पत्नी को लेकर तंज कसा है। ट्रम्प ने कहा कि मैक्रों अब भी जबड़े पर पड़े थप्पड़ से उबर रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करती हैं। ट्रम्प ने मैक्रों पर यह टिप्पणी बुधवार को एक प्राइवेट लंच के दौरान की। ट्रम्प का यह वीडियो कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर दिखा, लेकिन बाद में हटा दिया गया।

चेक बाउंस केस में सुनवाई के दौरान भावुक हुए राजपाल

बोले- पांच बार और जेल भेज दो, कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से मना किया

मुबंई, एजेंसी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बकाया रकम चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए राजपाल भावुक हो गए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने 6 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 30 दिन का समय देने की मांग ठुकराते हुए कहा, "नहीं मतलब नहीं। फैसला सुरक्षित रखा जा रहा है और समय नहीं मिलेगा।" कोर्ट ने कहा, "आप कह रहे हैं कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके वकील कह रहे हैं कि जेल जा चुके हैं, इसलिए पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो फिर मामले की सुनवाई क्यों हो रही है। पेमेंट कर दीजिए।" मामले में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने कोर्ट में कहा कि सजा पूरी करने से वित्तीय देनदारी खत्म नहीं होती। वकील अवनीत सिंह सिक्का ने दलील दी कि राजपाल यादव 10 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं करने की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पेमेंट न होने के बाद ही कार्यवाही शुरू की गई। कुल 7.75 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट से पहले करीब 2 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वन-टाइम सेटलमेंट की संभावना भी तलाशी। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि कम समय में 6 करोड़ रुपए दिए जाएं तो विवाद सुलझ सकता है, जिस पर शिकायतकर्ता भी सहमत दिखा। राजपाल यादव ने कहा, "उन्होंने मुझसे 17 करोड़ रुपए ले लिए हैं। मेरे पांच फ्लैट बेचने पड़े हैं। मैं फिर से कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं।

कहानी में ज्यादा बदलाव किया गया, तो लोग फिल्म को स्वीकार नहीं करेंगे

विंदू दारा सिंह ने 'रामायण' के मेकर्स को दी सलाह

मुबंई, एजेंसी

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर एक्टर विंदू दारा सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म के विजुअल्स शानदार हैं, लेकिन अगर कहानी में ज्यादा बदलाव हुआ तो दर्शक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' (1987) में विंदू के पिता दारा सिंह ने हनुमान का रोल निभाया था। विंदू ने यह भी कहा कहा कि अगर कहानी में ज्यादा बदलाव किया गया, जैसे इसमें वो खतरनाक (असुर) से दिख रहे हैं, तो अगर ज्यादा ऊपर-नीचे किया, तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। विंदू दारा सिंह ने टेलीविजन शो (जय वीर हनुमान) और कई रामलीलाओं में भगवान हनुमान की भूमिका निभाई है। विंदू ने फिल्म के विजुअल्स की तारीफ करते हुए कहा कि नमित मल्होत्रा विजुअल्स को बेहतर तरीके से पेश करना जानते हैं।

आदिपुरुष से बेहतर बताई नई रामायण

विंदू दारा सिंह ने कहा कि अब तक जो देखा गया है, उसके आधार पर यह फिल्म आदिपुरुष से बेहतर लग रही है। उन्होंने कहा कि पहले की रामायण और महाभारत सीरियल ने एक मानक तय किया है, जिससे तुलना होना स्वाभाविक है।

- फिल्म रामायण में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का लुक।
- विंदू दारा सिंह ने टेलीविजन शो (जय वीर हनुमान) और कई रामलीलाओं में भगवान हनुमान की भूमिका निभाई है।

डीएनए से बातचीत में फिल्म रामायण को लेकर विंदू ने कहा कि यह बहुत शानदार दिख रही है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक सख्त नियम है। जो रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई है, वह हम सबके दिल और दिमाग में पूरी तरह बसी हुई है। वह रामायण ऐतिहासिक है, नंबर वन है। अगर यह फिल्म उसके लेवल से मेल खा गई, तो यह सुपरहिट होगी। यह एक रिकॉर्ड तोड़ हिट साबित होगी।

विंदू ने रणबीर की तारीफ की

विंदू ने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि वह राम के रूप में अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के लिए अरुण गोविल की इमेज अब भी राम के रूप में जुड़ी हुई है, जबकि उनके पिता दारा सिंह हनुमान के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब नए कलाकार वही किरदार निभा रहे हैं और अरुण गोविल इस फिल्म में दशरथ की भूमिका में सही हैं। विंदू ने उम्मीद जताई कि अगर अभिनय और प्रस्तुति सही रही तो फिल्म सक्सेस हो सकती है।

24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल, काश पटेल-तुलसी गबार्ड को भी हटाने की चर्चा

जंग के बीच ट्रम्प सरकार में उथल-पुथल

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रम्प सरकार में कुछ और बड़े अफसरों को निकाले जाने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगला नंबर FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का हो सकता है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के प्लान से जुड़े कई लोगों ने बताया कि और भी अधिकारियों को हटाने पर चर्चा चल रही है। इसमें आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज-डीरेमर का नाम भी शामिल है। इसी दबाव में बॉन्डी ने कुछ लोगों को व्हाइट हाउस बुलाया और उन्हें एपस्टीन फाइल्स फेज 1 नाम का फोल्डर दिया। फोल्डर देने के बाद मामला उल्टा बॉन्डी के लिए परेशानी बन गया। दरअसल उम्मीद थी कि कोई बड़ी जानकारी या खुलासा सामने आएगा। लेकिन जब लोगों ने उन्हें देखा, तो पता चला कि उनमें कोई नई या चौंकाने वाली जानकारी नहीं थी। इससे एपस्टीन का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। फिर ऐसी स्थिति बन गई कि खुद ट्रम्प को इसे जारी करने वाले बिल पर साइन करना पड़ा। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया गया है। CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह आदेश दिया।

क्रिस्टी नोएम- बर्खास्त होने वाली पहली अधिकारी

ईरान से जंग के बीच अमेरिकी सरकार में तेजी से प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी चीफ क्रिस्टी नोएम को बेदखल किए जाने से इसकी शुरुआत हुई। उन्हें किस वजह से हटाया गया इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई वजह नहीं बताई गई है। कुछ समय से उनकी काम करने की शैली और फैसलों पर सवाल उठ रहे थे। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की जिम्मेदारी होती है।

- ट्रम्प ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का चीफ बनाने के लिए नामित कर दिया था।

एपस्टीन पर आरोप था कि वह नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था और एक बड़ा नेटवर्क चलाता था, जिसमें ताकतवर और अमीर लोग शामिल हो सकते थे। इसी वजह से लोग यह जानना चाहते हैं।

पैम बॉन्डी- एपस्टीन फाइल्स की भेंट चढ़ीं

व्हाइट हाउस के एक करीबी ने द अटलांटिक से कहा कि क्रिस्टी नोएम को हटाने पर जो प्रतिक्रिया मिली, उससे ट्रम्प को हिम्मत मिली और उन्होंने बॉन्डी को हटाने का फैसला आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि पैम बॉन्डी ने एपस्टीन मामले को ठीक से नहीं संभाला। दरअसल, एपस्टीन मामले से जुड़ी सच्चाई सामने लाने की मांग लंबे समय से हो रही थी, खासकर 'क्लाइंट लिस्ट' को लेकर, जिसमें यह बताया जाता है कि किन-किन प्रभावशाली लोगों का उससे संबंध था।

पाकिस्तान में गाय-भैंस पालने पर गोबर टैक्स लगाने की तैयारी

हर पशु पर रोजाना 30 रुपए वसूलेगी सरकार

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान के पंजाब राज्य में गाय और भैंस पालने पर अब 'गोबर टैक्स' लगाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज की सरकार हर गाय और भैंस पर रोजाना 30 पाकिस्तानी रुपए फीस देने का नियम बना सकती है। सरकार इस कदम को ग्रीन एनर्जी के रूप में पेश कर रही है। यह योजना 'सुथरा पंजाब' बायोगैस प्रोग्राम का हिस्सा बताई जा रही है। यह प्रोग्राम दिसंबर 2024 में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। इसका मकसद कचरे को साफ करना और उससे बायोगैस बनाकर ऊर्जा तैयार करना है। वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना कर इसे 'गोबर टैक्स' का नाम दिया है। उनका कहना है कि यह कदम दिखाता है कि सरकार आर्थिक दबाव में है और अब नए-नए तरीकों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने दावा किया कि 'ग्रीन एनर्जी' का नाम बस दिखावा है। असली कहानी कुछ और है। सरकार का फैसला पहले से महंगाई और महंगे चारे से जूझ रहे किसानों से जबरन पैसा निकालने का तरीका है। सरकार ने इस फीस को लागू करने के लिए राज्य की करीब 168 कैटल कॉलोनियों को चिन्हित किया है। इन कॉलोनियों की लगभग 50 लाख गाय-भैंसों पर यह फीस लग सकती है। इस नई योजना के तहत पशुपालकों से हर पशु के हिसाब से रोजाना शुल्क लिया जाएगा। पहले चरण में लाहौर की दो प्रमुख डेयरी कॉलोनियों हरबंसपुरा और गुज्जरपुरा से शुरू होगा। बाद में पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा।

तैयारी: एयरलाइंस के साथ जल्द मीटिंग करेगी, एटीएफ के दाम दोगुने, इंडिगो की उड़ानें 10,000 तक महंगी

हवाई किराया बढ़ाया तो सरकार दखल देगी

नई दिल्ली, एजेंसी

एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद कई एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इससे यात्रियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की तैयारी में है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जल्द ही एयरलाइंस के साथ मीटिंग कर सकती है ताकि आम लोगों को महंगे सफर से राहत मिल सके। सरकार ने अभी तक कोई लिखित निर्देश तो जारी नहीं किया है, लेकिन एयरलाइंस से उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री किरायों में बढ़ोतरी न हो। एटीएफ की कीमतों में हाल ही में सोझ समझकर बढ़ोतरी की गई थी। सरकार ने एविएशन सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए कीमतों में कुल 25% की बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। हालांकि, आम यात्रियों को राहत देने के लिए घरेलू ऑपरेशंस के लिए प्रभावी बढ़ोतरी को करीब 8.5% तक ही सीमित रखा गया था। वहीं इंटरनेशनल ऑपरेशंस और चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए एटीएफ के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। यह 96,638.14 रुपए प्रति किलोलीटर से बढ़कर 2,07,341.22 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंच गया है। घरेलू एटीएफ की कीमत अब 1,04,927.18 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। भले ही सरकार ने घरेलू स्तर पर बोझ कम रखने की कोशिश की, लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज में बदलाव किया। इंडिगो ने पहले के 425 रुपए के फ्लैट सरचार्ज को हटाकर अब दूरी के हिसाब से नया स्ट्रक्चर लागू किया है। डोमेस्टिक रूट्सः अब दूरी के आधार पर 275 रुपए से लेकर 950 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगेगा। कम दूरी की उड़ानों के लिए यह राहत की बात है, लेकिन लंबी दूरी की घरेलू उड़ानें महंगी हो गई हैं।

सरकार के हस्तक्षेप से क्या किराया कम होगा?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार के दखल के बाद एयरलाइंस को अपने बढ़े हुए सरचार्ज पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि एयरलाइंस पूरा बोझ ग्राहकों पर न डालें, बल्कि इसे धीरे-धीरे एडजस्ट करें। अगर बातचीत सफल रहती है, तो आने वाले दिनों में कुछ रूट्स पर सरचार्ज में कटौती या रोलबैक देखने को मिल सकता है।

एटीएफ कीमतों में बदलाव

कैटेगरी	पुरानी कीमत (प्रति किलोलीटर)	नई कीमत (प्रति किलोलीटर)	बदलाव
इंटरनेशनल एटीएफ	96,638	2,07,341	+114%
डोमेस्टिक एटीएफ	96,638	1,04,927	+8.5%

एविएशन सेक्टर के जानकारों का कहना है कि किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट (परिचालन लागत) में फ्यूल का हिस्सा करीब 40% होता है। ऐसे में एटीएफ की कीमतों में मामूली बदलाव भी एयरलाइंस के मुनाफे पर सीधा असर डालता है। एयरलाइंस का तर्क है कि लागत बढ़ने की वजह से वे इस बोझ को यात्रियों पर डालने के लिए मजबूर हैं।

क्या होता है फ्यूल सरचार्ज?

जब तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ जाती हैं, तो एयरलाइंस बेस फेयर (आधार किराया) बढ़ाने के बजाय टिकट पर एक अतिरिक्त शुल्क जोड़ देती हैं, जिसे फ्यूल सरचार्ज कहते हैं। तेल की कीमतें कम होने पर इसे घटाया या हटाया जा सकता है।

ओटीपी के बिना हो सकेगा ऑनलाइन पेमेंट

बैंक-टेलीकॉम कंपनियां 'साइलेंट ऑथेंटिकेशन' लाएंगी, सिम-डिवाइस मैच नहीं हुए तो रुकेगा ट्रांजैक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी

देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां 'साइलेंट ऑथेंटिकेशन' तकनीक पर काम कर रही हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम बैकग्राउंड में ही चेक कर लेगा कि बैंक एप में रजिस्टर्ड नंबर और फोन का सिम कार्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर सिम और नंबर मैच नहीं हुए, तो ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। यह तकनीक ई-सिम (eSIM) पर भी काम करेगी। इससे सिम क्लोनिंग और ई-सिम स्वैप जैसे फ्रॉड रुकेंगे। यह जानकारी एक्सिस बैंक के डिजिटल बिजनेस हेड समीर शेट्टी ने दी। PWC इंडिया के साइबर लीडर सुंदरेश्वर कृष्णमूर्ति के मुताबिक, अब तक सुरक्षा की परतें ऐसी थीं, जिन्हें आसानी से हैक किया जा सकता था। अब बैंक और टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क के मुख्य हिस्से में ही वेरिफिकेशन को शिफ्ट कर रही हैं। यह सिस्टम बैकग्राउंड में काम करेगा, जिसे यूजर या हैकर नहीं देख सकेंगे। सुरक्षा को पक्का करने के लिए इसमें फेस ID और एप के अंदर ही कोड (OTP) जनरेट होने जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। नए नियमों के बाद अब बैंक OTP भेजने के लिए वॉट्सएप जैसे थर्ड-पार्टी एप्स का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अनुमान है कि हर महीने करीब 1000 करोड़ ट्रांजैक्शनल मैसेज भेजे जाते हैं। क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी सिंच के MD नितिन सिंघल ने कहा कि इस बदलाव से ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा और ट्रांजैक्शन फेल होने की दर भी कम होगी ब्रांड्स के लिए भी यह फायदेमंद होगा, क्योंकि चेकआउट प्रक्रिया आसान होने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और डिजिटल एडॉप्शन तेज होगा। हालांकि SMS वाले OTP को बंद नहीं किया गया है, लेकिन बैंकों को अब फिंगरप्रिंट और डिवाइस की अपनी सुरक्षा जैसे आधुनिक तरीके इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

शेट्टी ने बताया, 'हम टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर साइलेंट ऑथेंटिकेशन के कई पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति एप में लॉग-इन है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नंबर से मैच नहीं करता, तो टेलीकॉम नेटवर्क हमें इसका सिग्नल दे देगा।

सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 14 अप्रैल को गांव-गांव मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती

भाजपा 'सौदागर' की तरह कर रही काम, महंगाई-बेरोजगारी चरम पर: अखिलेश

तमसा संकेत,संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार "सौदागर" की तरह काम कर रही है और देश की संपत्तियों को बेचने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है, जिससे महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ रहे हैं, जबकि पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बताया कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2026 को सेक्टर और गांव स्तर पर मनाई जाएगी। इस दौरान संविधान पर कथित संकट और उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान देश की बुनियाद है और भाजपा उस बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं और युवाओं की आवाज दबा रही है। उन्होंने डायल 100 की महिला कर्मचारियों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया।

> अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान समय "अमृत काल" नहीं बल्कि "संकट काल" है। उन्होंने आरोप लगाया कि संतों के साथ अन्याय हो रहा है और समाज में असुरक्षा का माहौल है। सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहब के संविधान, राम मनोहर लोहिया के विचारों और नेताजी की समाजवादी सोच के रास्ते पर चलकर समाज को नई दिशा देना चाहती है।

शिक्षा और तकनीक पर समाजवादी सरकार के काम गिनाए

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान छात्रों को लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं, जिससे खासकर कोविड काल में छात्रों को काफी मदद मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय लोगों को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की ओर धकेल रही है।

कानून व्यवस्था पर सवाल, अपराध बढ़ने का आरोप

अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं और सरकार नियंत्रण में विफल है। उन्होंने गोरखपुर समेत कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति खराब है और गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मरीजों को सही इलाज और दवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

कल्याण मंडपों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने शहर के कल्याण मंडपों और सामुदायिक केंद्रों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को इसका उद्घाटन जोन-1 के झंडेवाला पार्क में 29.62 करोड़ रुपए से किए गए विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान किया गया। मेयर ने 456 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें शहर की सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, नालियों की मरम्मत, पार्कों का सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मेयर सुषमा खर्कवाल द्वारा एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए कल्याण मंडपों और सामुदायिक केंद्रों की ऑनलाइन बुकिंग के पोर्टल पर लिंक का शुभारंभ किया गया। इस नई व्यवस्था के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे ही मंडपों की उपलब्धता देख सकेंगे और ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। सामुदायिक केंद्र/कल्याणमंडप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट https://lmc.up.nic.in/ पर आवेदन करें। मेयर सुषमा खर्कवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह अवसर उनके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है।

यूपीपीसीएल की सेवाएं 16-घंटे के लिए बंद रहेंगी

रात 10 से दोपहर 2 बजे तक नहीं होंगे काम, समय से जमा कर लें बिल

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए आज यानी 3 अप्रैल रात 10 बजे से 4 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक बिलिंग सेवा, ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल और UPPCL कंज्यूमर ऐप काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसकी एडवाइजरी जारी की है। 16 घंटे तक बिजली उपभोक्ता बिलिंग भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज, बिल जनरेशन, भार वृद्धि जैसे काम भी नहीं हो सकेंगे। हालांकि 3 अप्रैल शुक्रवार को सार्वजनिक छुट्टी है। इस दिन बिजली विभाग में न तो बकाएदारों की बिजली कटती है और न ही कोई काम होता है। इसलिए इस दिन को मरम्मत कार्य के लिए चुना गया है। 4 अप्रैल यानी शनिवार सुबह 10 बजे के बाद ही बकाएदारों के कनेक्शन काटने का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने अपनी आरएमएस (Revenue Management System) बिलिंग प्रणाली में मेंटेनेंस और कॉन्फिगरेशन कार्य के कारण अस्थाई रूप से बंद करने का फैसला लिया है। इससे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और केस्को (Kanpur Electricity Supply Company) के इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

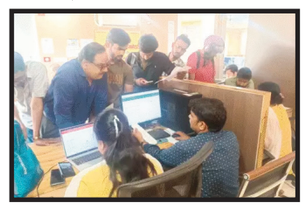

> यूपीपीसीएल की उपभोक्ताओं से अपील समय रहते चेक कर लें अपना बकाया बिल।

फास्ट न्यूज़

सर्राफ को लूटने वालों का एनकाउंटर

कानपुर। कानपुर में सर्राफ से लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे में एनकाउंटर में पकड़ लिया। मुठभेड़ में पुलिस ने दो बदमाशों के पैर में गोली मारकर दबोच लिया, जबकि एक को दौड़ाकर अरेस्ट किया। तीनों लुटेरों ने बुधवार रात ग्वालटोली में एक सर्राफ से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की पहचान करने के बाद मुठमेड़ में अरेस्ट कर लिया।

सर्राफ को लूटने वालों का एनकाउंटर

गोंडा। गोंडा जिले के खोण्डारे थाना क्षेत्र के बैजपुर गांव में एक महिला ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची को नदी में फेंक 4 वर्षीय बेटी को गोद में लेकर कुआनो नदी में छलांग लगा दी है। इस घटना में डेढ़ वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला और उसके चार वर्षीय बेटे को बचा लिया खोण्डारे पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय सोनम का अपने पति मदनलाल से पारिवारिक विवाद हुआ था। विवाद के बाद देर रात सोनम अपने दो बच्चों, डेढ़ वर्षीय अंशी और चार वर्षीय आयुष, के साथ राजघाट पुल पहुंची। वहां उसने पहले बच्ची अंशी को नदी में फेंका, फिर बेटे आयुष को गोद में लेकर खुद छलांग लगा दी। उसी समय वहां से गुजर रहे दो राहगीरों ने यह देखा और तुरंत नदी में कूदकर महिला व उसके बेटे को बचाया।

भाभी ने गंगाजल लेकर कसम खाई, प्रेमी ने गला रेता

गोरखपुर। गोरखपुर में महिला की गला रेतकर हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, महिला खुशबू (28) और हत्यारोपी सीताराम (28) के बीच अफेयर था। खुशबू के घरवालों को जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों को समझाया। 3 बार पंचायत भी हुई। सीताराम का घर खुशबू के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। इस वजह से खुशबू के देवर जितेंद्र (26) और सीताराम के बीच अच्छी दोस्ती थी।

ढाई लाख वसूली के मामले में थानेदार लाइन हाजिर

ढाई लाख रुपए वसूली के आरोप के बाद एक्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में गौतमपल्ली थाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गौतमपल्ली थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि थाने के अन्य दरोगा-सिपाहियों की भूमिका की जांच चल रही है। थाने के SHO रत्नेश सिंह सहित यहां के सभी सिपाहियों पर ढाई लाख रुपए वसूली का आरोप है। सीपी (पुलिस कमिश्नर) की जांच के बाद पूरे थाने पर शुक्रवार को एक्शन ले लिया गया। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले रात में बंदरिया बाग चौकी इंचार्ज एक युवक को पकड़कर थाने लाए थे। वहां उससे करीब ढाई लाख रुपए की वसूली की गई। इस गंभीर भ्रष्टाचार प्रकरण की जांच पुलिस कमिश्नर से कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। कार्रवाई में इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। वहीं, थाने की नई कमान विपिन सिंह को सौंपी गई है। सीएम आवास क्षेत्र के थाने पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। थाने के सूत्रों के अनुसार, दो दिन पहले जिस युवक को गौतमपल्ली थाने पर लाया गया था, उसकी आमद (एंट्री) जनरल डायरी (जीडी) में दर्ज की गई। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित व्यक्ति की थाने में विधिवत एंट्री दर्ज है। पूछताछ के बाद उसे रिहा किया गया था। इस बीच रुपए के लेन-देन की बात सामने आने के बाद पुलिस महकमे में जांच कर रहा है।

चाचा-भतीजे को 20 मिनट रौंदती रहीं गाड़ियां, मौत

मैनपुरी। मैनपुरी में डंपर ने बाइक सवार चाचा-भतीजा समेत तीन लोगों को रौंद दिया। चाचा-भतीजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों के शव सड़क पर ही पड़े रहे। करीब 20 मिनट तक दोनों शवों के ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं।

गांववालों की सूचना पर पुलिस पहुंची। बुरी तरह से कुचल चुके शवों को किसी तरह समेटा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। जबकि गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

घटना गुरुवार रात 10.30 बजे किशनी थाना के NH-92 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की है। बाइक सवार तीनों किशनी थाना के जटपुरा गांव में एक शादी समारोह में गए थे। लौटते हुए रास्ते में हादसा हुआ। मृतक कन्नौज जिले के छिबरामऊ के रहने वाले थे।

पुलिस ने तीनों की पहचान जेब से मिले ड्राइविंग लाइसेंस से की। घायल आफताब के मोबाइल फोन से पुलिस ने परिजन को फोन कर हादसे की जानकारी दी। मृतक वसीम के भाई नदीम ने बताया कि फुटपाथ पर वसीम पर्स-बेल्ट की दुकान लगाते थे, जबकि सत्तार की सब्जी की दुकान थी और आफताब बिरयानी बेचते थे।

वेतन विवाद में नया मोड़, पुलिसवालों ने जबरन बस में बैठाया, कार्रवाई के डर से छिपते फिर रहे कर्मचारी

1076 के कर्मियों का प्रदर्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में 1076 से जुड़े कर्मचारियों का प्रदर्शन अब तेज हो गया है। साइबर टॉवर में हुए हंगामे के बाद कई कर्मचारी पुलिस कार्रवाई के डर से इधर-उधर छिपते नजर आए। बताया जा रहा है कि एक महिला कर्मचारी खुद को बचाते हुए कामता बस स्टैंड तक पहुंचे, जबकि अन्य कर्मचारी अलग-अलग जगहों पर छिपकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी भर्ती ₹15,000 वेतन पर की गई थी, तो उन्हें आधी सैलरी क्यों दी जा रही है। उनका आरोप है कि न सिर्फ वेतन कम दिया जा रहा है, बल्कि भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा। 60 दिन बाद भी पूरी सैलरी नहीं दी गई और कई महीनों का भुगतान अब भी बकाया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) जो आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई थी, अब अपने ही कर्मचारियों के विरोध का सामना कर रही है।

चार महीने से बकाया वेतन, कर्मचारियों में बढ़ता आक्रोश

कर्मचारियों के मुताबिक पिछले चार महीनों से उनका वेतन बकाया है। लगातार काम लेने के बावजूद भुगतान न होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बार-बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना। कर्मचारियों का कहना है कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपने हक की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है- "अगर हमें 15,000 में भर्ती किया गया था, तो 7-8 हजार क्यों दिए जा रहे हैं? हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने के बजाय दबाव बनाया जा रहा है।"

> कर्मचारियों का कहना था कि 15 हजार रुपए की सैलरी का वादा करके 7000-8000 रुपए दिए जा रहे हैं। सैलरी भी रोककर दी जा रही है।

50 से ज्यादा कर्मचारी अब भी डटे करीब 50 से ज्यादा कर्मचारी अब भी विरोध में डटे हुए हैं और प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 10 घंटे का समय दिया गया था।

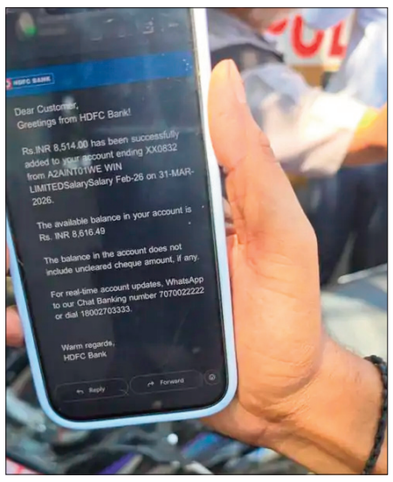

> कर्मचारियों ने सैलरी दिखाई। उनका कहना है कि उन्हें 15 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से सैलरी देने की बात थी, लेकिन अब किसी को 7 हजार तो किसी को 8 हजार रुपए के आसपास पैसे दिए जा रहे हैं।

युवा शक्ति के दम पर 2027 में बदलाव का आह्वान

लखनऊ में सपा युवा संगठनों की बैठक, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का दिया संदेश

तमसा संकेत,संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा शासन में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है और भ्रष्टाचार व लूट का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पार्टी के युवाओं से आह्वान किया कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ बूथ स्तर तक सक्रिय हों। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में, जो डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में हुई, सपा के विभिन्न युवा संगठनों के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी को युवा शक्ति पर पूरा भरोसा है और यही शक्ति आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकजुटता से घबराई हुई है और इसी कारण वह समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। सपा प्रमुख ने युवाओं को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि भाजपा की कथित साजिशों को समझकर उन्हें विफल करना होगा। अखिलेश यादव ने भाजपा को "षड्यंत्रकारी पार्टी" बताते हुए आरोप लगाया कि वह समाज में नफरत और भेदभाव फैलाती है तथा सामाजिक न्याय की अनदेखी करती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी वर्गों को समान अधिकार व सम्मान मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय शुरू की गई 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं, डायल 100 क्विक रिस्पांस सिस्टम (जिसे अब 112 में बदला गया है), आधुनिक पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती रिवर फ्रंट और मेट्रो रेल जैसी परियोजनाएं प्रदेश के विकास की पहचान थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से अपील की कि वे जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हों और अपने व्यवहार व भाषा में संयम व सम्मान बनाए रखें। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा आपसी सम्मान और भाईचारे पर आधारित है, जिसे मजबूत करना आवश्यक है।

वारदात : 4 महीने की गर्भवती, खिलौना पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी लूटी, बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार

बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली

तमसा संकेत, एजेंसी

अयोध्या। अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला हिंदू निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने वारदात की थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम पायल (25) और लड़के का नाम राहुल (27) है। वारदात के वक्त राहुल ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.6 लाख का सोने का हार और चेन लूट ली। फिर भागकर राहुल के पास पहुंची। उसके साथ बाइक से फरार हो गई। आरोपी पायल की पिछले साल 5 अप्रैल को शादी हुई थी। वह 4 महीने की गर्भवती है। पति के साथ पंजाब में रह रही थी। 16 अप्रैल को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए अयोध्या में मायके आई थी। पायल के पिता राम नवल ने को बताया कि गुरुवार को ताबीज बनवाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसने बताया था कि उसकी तबीयत बार-बार खराब हो जाती है। उसने यह सब क्यों किया, नहीं पता। वारदात गुरुवार दोपहर 12.30 बजे हुई। ज्वेलरी की दुकान में लगे 6 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। घटना रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोठी बाजार की है। राम मंदिर से घटनास्थल की दूरी करीब 45 किमी है। शुरुआती जांच में पता चला कि राहुल ने बाजार से नकली पिस्टल और बुर्का खरीदा। पहचान छिपाने के लिए पायल ने बुर्का पहनकर वारदात की। जिस बाइक से दोनों फरार हुए थे, कैमरे में उसका नंबर कैद हो गया था। इसे ट्रेस कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

> एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार ने बताया- दोनों अयोध्या से बाहर भागने की फिराक में थे। तभी गिरफ्तार कर लिया गया। बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला का नाम पायल है। उसके साथ राहुल नाम का लड़का था, दोनों बंटी और बबली बनकर घटना को अंजाम दे रहे थे।

बुर्का पहनकर सोने का हार और चेन खरीदने पहुंची थी

रुदौली क्षेत्र के कोठी बाजार मोहल्ला के रहने वाले महेश सर्राफा व्यापारी हैं। उनकी घर से 900 मीटर दूर अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। गुरुवार दोपहर को बुर्का पहने एक महिला पहुंची। उसके बाद एक पिट्ठू बैग था। दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार महेश से कहा- मुझे सोने का हार और चेन खरीदनी है। महेश ने उसके सामने एक सोने का हार और सोने की चेन रख दी।

कमर से पिस्टल निकाली, बोली- आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी

दुकानदार महेश ने उसे टोका तो उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली। महेश की ओर तानकर बोली- आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। इसके बाद वह दुकान के बाहर भाग गई। महेश और मनीराम ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया था।

पृष्ठ 01 का शेष...

'खामोश करवाया ...

इसके बाद उन्होंने सदन में उठाए गए नेशनल मुद्दों को लेकर भी वीडियो शेयर किया। उधर, AAP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा कि राघव सदन में पार्टी के मुद्दे उठाने के बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की बात करते उठाते थे। सदन में पार्टी के लाए प्रस्ताव पर भी उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए? पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राघव चड्ढा को कंप्रोमाइज्ड करार देते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। AAP ने गुरुवार को चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था। पंजाब से ही राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को उनकी जगह दे दी। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। लेटर में कहा कि चड्ढा को सदन में पार्टी की तरफ से बोलने का समय न दिया जाए। पार्टी ने इस फैसले की वजह नहीं बताई। राघव 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। हालांकि, राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी और AAP को लेकर कोई बयान नहीं दिया। यहां तक कि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के वक्त वह UK में थे। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के बरी होने पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था। राज्यसभा में AAP के नए उपनेता बनाए गए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के वाइस चांसलर सांसद अशोक मित्तल ने कहा था कि मेरा मुख्य फोकस सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना होगा। राघव चड्ढा की तरह मुखर भूमिका में नजर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर नेता की अपनी अलग कार्यशैली और व्यक्तित्व होता है। मैं अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के अनुसार काम करूंगा, न कि किसी की शैली को दोहराने की कोशिश करेंगे। चड्ढा ने कहा कि 5 नदियों वाला सूबा पंजाब पानी की उपलब्धता और क्वालिटी के मामले में सबसे बड़ी मार झेल रहा है। सरकार से अनुरोध किया कि हर छोटे-बड़े एयरपोर्ट पर चेक इन के बाहर वाले एरिया में कैफे की शुरुआत की जाए। भारत के शहरों में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। राघव चड्ढा की तरह मुखर भूमिका में नजर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर नेता की अपनी अलग कार्यशैली और व्यक्तित्व होता है। मैं अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के अनुसार काम करूंगा, न कि किसी की शैली को दोहराने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन-रोजगार गैप पर चिंताः उन्होंने कहा कि भारत का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है, जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और झूठे विज्ञापन कहा जाता है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच गैप बहुत ज्यादा है, जिससे युवाओं को रोजगार पाने में दिक्कत हो रही है।

हमारे यहां सड़कों ...

कांग्रेस या यूडीएफ के लोगों को जब भी अवसर मिला, उन्होंने भारत और भारतीयता का लगातार अपमान किया है। यूडीएफ तो असम में घुसपैठ की जननी है। कांग्रेस उनके दम पर सरकार बनाना चाहती है। असम की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। लेकिन, एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम कर रही है। असम की बहनों, नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से पहचान का संकट खड़ा किया गया। मोदीजी के नेतृत्व ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। असम में भी डबल इंजन की सरकार आई, पहले सर्वानंद सोनोवाल और फिर हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी तो असम चिप उत्पादन का केंद्र बन गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, वो करके दिखाया है। मोदी जितनी बार पूर्वोत्तर में आए हैं, कांग्रेस का कोई पीएम नहीं आया होगा। मोदी ने 36 यात्रा कीं, तब यहां सुशासन और सुरक्षा का माहौल बना है।

असम में यूसीसी ...

जिससे बाहरी लोगों का राज्य में आना आसान हो सके। मालदा में दो दिन पहले न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर ममता बनर्जी ने AIMIM और ISF को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर उकसाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में भाजपा और कांग्रेस ने अपने 27-27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को अविनाशी (SC) सीट से टिकट दिया है। हालांकि इस लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई का नाम नहीं है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है।

मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से 'जंगल राज' खत्म कर दिया जाएगा। असम के नॉर्थ कामरूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां का माहौल देखकर लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है।

उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को लोग कमल को जिताकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अन्नामलाई का नाम सूची में नहीं होने पर उन्होंने कहा कि यह हाईकमान का फैसला है।

यूपी के एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा

5 से 85 रुपए तक अधिक टोल देने होंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी। यूपी के एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वालों के लिए 1 अप्रैल 2026 सफर महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने टोल की नए रेट लागू कर दिए हैं। आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल पर 5 रुपए से 85 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की गई है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तीनपहिया वाहनों का टोल 5 रुपए महंगा किया गया है। जबकि कार, जीप, वैन के लिए 10 रुपए अधिक टोल देना होगा। इसके अलावा भारी वाहनों पर 85 रुपए टोल अधिक देने होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहनों (दोपहिया और तिपहिया) के लिए राहत दी गई है। यहां टू-व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहनों के लिए टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यात्रियों को पहले की तरह ही 350 रुपए का पेमेंट करना होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी छोटे वाहनों (दोपहिया और तिपहिया) के लिए बड़ी राहत दी गई है। इस रूट पर भी छोटे वाहनों के लिए पुराने रेट ही लागू रहेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए आपको 315 रुपए खर्च करने होंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले कार चालकों के लिए थोड़ी बुरी खबर है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676